RNI NO. MPHIN/2022/85285
डाक पंजी.क्र. - MP/KDW/93/2026-28
राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र
हलधर किसान
KISAN PLUS TV | KISAN PLUS Radio
स्मार्ट किसान की पहली पसन्द Haldharkisankgn@gmail.com
वर्ष 5 अंक 05 | (मासिक) जुलाई | पृष्ठ-8 | मूल्य, 5 रुपये

भारत में हरित यूरिया उत्पादन का सपना साकार करने की तैयारी, बनाया रोड़मैप

नई दिल्ली।

भारत में हरित यूरिया की उत्पादन संभावनाएं मजबूत दिखाई दे रही है। उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, यूरिया कंपनियों ने इस दिशा में दिलचस्पी दिखाई है।

सरकार ने सतत कृषि, कार्बन तटस्थता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में उर्वरक विभाग ने भारत के पीडीआईएल में ग्रीन यूरिया प्लांट लगाने के लिए उच्च.स्तरीय प्री.एक्सप्रेशन ऑफइंटरेस्ट बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता डॉ. केके पाठक . संयुक्त सचिव उर्वरक विभाग ने की, जो पीडीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में, उर्वरक विभाग ने भारत में ग्रीन यूरिया प्लांट लगाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन ऑफइंटरेस्ट के लिए निमंत्रण जारी किया था। पीडीआईएल मुख्यालय, नोएडा में आयोजित प्री.ईओआई बैठक ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के कई हितधारकों के लिए बेहतरीन मंच प्रदान किया। इनमें एनटीपीसी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, अमोनिया.यूरिया टेक्नोलॉजी सप्लायर्स, प्रमुख भारतीय उर्वरक कंपनियां और इलेक्ट्रोलाइज़र, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने वाली कंपनियां शामिल थीं। पूरी वैल्यू चेन से संभावित कंपनियों की बड़ी संख्या में ऑनलाइन और ऑफलाइन उपस्थिति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसमें शामिल सभी लोग इस पहल को निकट भविष्य में हकीकत बनाने के लिए कितने उत्सुक हैं।

बता दें कि पारंपरिक यूरिया बनाने के लिए एलएनजी गैस का उपयोग होता है। वहीं, हरित यूरिया के उत्पादन में ग्रीन अमोनिया का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक यूरिया बनाने में प्रदूषण फैलाने वाली गैसों का उत्सर्जन होता है, लेकिन हरित यूरिया को बनाने में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन अमोनिया का उपयोग किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पिछले रबी सीजन से ही धान, तिलहन और गन्ने जैसी फसलों पर हरित अमोनिया के प्रभाव का परीक्षण कर रही है। आंध्र प्रदेश के पुदिमदका में एनटीपीसी द्वारा 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक हरित यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है। यह प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और पानी से हाइड्रोजन बनाने की आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा।

सरकार देगी भारी आर्थिक मदद

चूंकि ग्रीन यूरिया बनाना फिलहाल सामान्य खाद के मुकाबले महंगा है, इसलिए सरकार इसे सस्ता करने के लिए बड़ी वित्तीय मदद दे रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 19,744 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

उर्वरक मंत्रालय ऐसी व्यवस्था बना रहा है, जिसमें से की नाम की संस्था कंपनियों से ग्रीन अमोनिया खरीदेगी और उसे पुरानी कीमतों पर खाद कंपनियों को देगी। जो भी घाटा या अतिरिक्त खर्च होगाए उसे सरकार खुद वहन करेगी।

आयात पर निर्भरता होगी कम

भारत ने साल 2025-26 के दौरान करीब 100 लाख टन यूरिया का आयात किया था। सरकार की कोशिश है कि देश के भीतर ही उत्पादन बढ़ाकर इस निर्भरता को खत्म किया जाए। सरकार ने हर साल 7.24 लाख टन ग्रीन अमोनिया बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका आवंटन ऑनलाइन नीलामी के जरिए किया जाएगा।

प्रदूषण कम करने में मददगार

ग्रीन यूरिया बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांटए सीमेंट और स्टील प्लांट से निकलने वाली हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्चे माल के तौर पर किया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक, एक बड़े यूरिया प्लांट को चलाने के लिए हर साल करीब 10 लाख टन सीओ-2 की जरूरत होगी। इससे देश को 2070 तक शून्य प्रदूषण के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

नीति और परिचालन संबंधी मुख्य बातें-

1. मंत्रालयों के बीच समन्वित सरकारी सहयोगरू चर्चाओं में ग्रीन प्रोडक्शन को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए कई मंत्रालयों से मिलने वाले वित्तीय आवंटन पर ज़ोर दिया गया। बड़े स्तर पर फंडिंग की प्रतिबद्धताओं में ये शामिल हैं- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय- महत्वपूर्ण ग्रीन ऊर्जा अवसंरचना को तेज़ी से बढ़ाने और भारत की स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी को मज़बूत करने के लिए 19,744 करोड़।

उर्वरक विभाग- ग्रीन अमोनिया को राष्ट्रीय उर्वरक निर्माण शृंखला में आसानी से शामिल करने के लिए संस्थागत और बाज़ार.समानता ढांचा तैयार करने का काम सौंपा गया।

2. **अलग-अलग कीमत मैकेनिज़्म के ज़रिए निर्माताओं की सुरक्षा-** लागत की चुनौतियों से निपटने और स्थानीय उर्वरक इकाइयों की सुरक्षा के लिए, मज़बूत ऑफ्टेकर.साइड डिफरेंशियल प्राइसिंग मैकेनिज़्म की अलग.अलग कीमत व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की गई-

चुनौती- पारंपरिक ग्रे अमोनिया की तुलना में ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में अभी ज़्यादा लागत आती हैए जिससे बिना मदद के ग्रीन यूरिया प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाता।

समाधान- भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने उत्पादकों से ग्रीन अमोनिया खरीदने के लिए निविदा पहले ही जारी कर दी हैं। इसे घरेलू उर्वरक कंपनियों को स्टैंडर्ड मार्केट.लिंक्ड ग्रे अमोनिया की कीमतों और दो हफ़्ते के औसत, साथ ही सीमा शुल्क और स्थानीय परिवहन लागत के आधार पर पर सप्लाई किया जाएगा। ग्रीन यूरिया के लिए भी कुछ इसी तरह के सिस्टम पर विचार किया जा सकता है।

3. **धीरे-धीरे कम होने वाली मदद के साथ उत्पादक.पक्ष के लिए प्रोत्साहन-** निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, एनजीएचएम ;ग्रीन अमोनिया मोड 2- के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन योजना का विवरण दिया गया। एसईसीआई द्वारा प्रबंधित पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी ई.रिवर्स नीलामी के ज़रिए कुल 7.24 लाख एमटी/ वर्ष ग्रीन अमोनिया की खरीद का लक्ष्य तय किया जाएगा। परियोजना के स्पष्ट चरणों में मदद दी जाएगी-

विकास चरण- नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं या निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए।

परिचालन चरण- वाणिज्यिक आपूर्ति की तारीख से नकद प्रोत्साहन शुरू होंगे।

दीर्घावधि निश्चितता- एक बाध्यकारी निश्चित समझौते के ज़रिए 10 वर्ष की अवधि के लिए लाभ सुरक्षित किए जाते हैं, जिससे डेवलपर्स को बाज़ार में मज़बूत भरोसा मिलता है।

विवादों में घिरी केंद्रीय मंत्री को मिली 99 लाख की सब्सीडी

खीरे की खेती के मंत्री बने लाभार्थी भी! 3765 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी को उनके ही मंत्रालय की एक योजना के तहत 99.60 लाख की सब्सिडी मिलने का मामला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे हितों का टकराव बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं, मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कोई तथ्य नहीं छिपाया और वर्ष 2018 में हजारों किसानों की तरह ही इस योजना के लिए आवेदन किया था।

मंत्री बोले. मैं बचपन से किसान

नई दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अजमेर से सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी को वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत खीरा खेती के लिए 99.60 लाख की सब्सिडी मिली। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस योजना को मंजूरी देने वाले बोर्ड में मंत्री पदेन उपाध्यक्ष हैं, जिसके बाद हितों के टकराव को लेकर सवाल उठने लगे।

विवाद बढ़ने पर भगीरथ चौधरी ने कहा कि वे बचपन से खेती करते आए हैं और उन्होंने कुछ भी छिपाया नहीं है। उन्होंने कहा मैं किसान हूं और बचपन से खेती कर रहा हूं। हजारों किसान पॉलीहाउस लगाकर सब्सिडी लेते हैं, मैंने भी 2018 में आवेदन किया था। अपने खेत पर बोर्ड लगाकर सभी ऋण और सब्सिडी की जानकारी सार्वजनिक की है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खेत पर स्थानीय अधिकारी कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। वहां किसानों को नई कृषि तकनीकों और प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

कांग्रेस ने बताया हितों का टकराव

कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस मामले में आवेदक भी वही, मंजूरी देने वाली व्यवस्था का हिस्सा भी वही और लाभार्थी भी वही हैं।

उन्होंने इसे हितों के टकराव का गंभीर उदाहरण बताते हुए सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। खेड़ा ने कहा कि एक ओर गरीबों को मुफ्त राशन और मध्याह्न भोजन को सरकारी कृपा की तरह पेश किया जाता है, जबकि दूसरी ओर मंत्री और प्रभावशाली लोग सरकारी योजनाओं का बड़ा लाभ उठा रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का सरकार पर हमला

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का नया मॉडल और हितों के टकराव का मामला बताते हुए कहा कि यदि कोई केंद्रीय मंत्री अपने ही मंत्रालय की योजना के तहत अपने खेत के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त करता है तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं।

गहलोत ने आरोप लगाया कि जहां एक ओर सामान्य किसान सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाता है वहीं दूसरी ओर मंत्री और प्रभावशाली अधिकारियों को करोड़ों रुपये की सरकारी सहायता आसानी से मिल जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देने की मांग करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए गए नारों और मौजूदा घटनाओं के बीच विरोधाभास दिखाई देता है।

आईएएस अधिकारी के परिवार का भी नाम

मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में सचिव और 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार के परिवार के सदस्यों को भी इसी योजना के तहत पांच वर्षों में कुल 1.16 करोड़ से अधिक की सब्सिडी मिली। रिपोर्ट के अनुसार, लाभार्थियों में उनकी पत्नी, मां और पुत्र भी शामिल हैं। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने योजना की पारदर्शिता और पात्रता प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।

अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर

फिलहाल केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी का कहना है कि उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए वर्षों पहले आवेदन किया था और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। वहीं विपक्ष इस मामले को हितों के टकराव और नैतिक जवाबदेही का मुद्दा बना रहा है। ऐसे में यह विवाद आने वाले दिनों में और राजनीतिक तूल पकड़ सकता है।

तीन महीने पहले 99.60 लाख रुपये की सब्सिडी मिली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को तीन महीने पहले 99.60 लाख रुपये की सब्सिडी मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सब्सिडी उसी मंत्रालय की एक योजना के तहत दी गई, जिसमें वह मंत्री हैं। इतना ही नहीं, जिस बोर्ड ने इस परियोजना को मंजूरी दी, उसके पदेन उपाध्यक्ष भी भागीरथ चौधरी ही है। यही बात अब विवाद की वजह बन गई है।

यह योजना बड़े पैमाने पर सब्जियों और फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड करता है, जो कृषि मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। मंत्रालय फिलहाल भागीरथ चौधरी के जिम्मे है।

सब्सिडी प्रस्तावों पर फैसला कौन लेता है?

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अन्य सदस्यों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिवए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और बागवानी क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी व उद्योग प्रतिनिधि शामिल हैं। यही बोर्ड विभिन्न परियोजनाओं और सब्सिडी प्रस्तावों पर फैसला लेता है। कागजों के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया है कि इस योजना के तहत सब्सिडी वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने में कृषि राज्य मंत्री की कोई सीधी भूमिका नहीं होती। अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की परियोजना अनुमोदन समिति देती है। इस समिति में बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते। ऐसे में तकनीकी रूप से परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया में मंत्री की सीधी भागीदारी नहीं मानी जाती।

इस मामले पर जवाब लेने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस ने भागीरथ चौधरी को सवालों की एक सूची भेजी थी। उनसे पूछा गया था कि क्या अपने ही मंत्रालय की योजना के तहत सब्सिडी लेना हितों के टकराव का मामला माना जा सकता है। खबर प्रकाशित होने तक भागीरथ चौधरी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के दीदवाना-कुचामन जिले के पीह गांव में चौधरी के फार्म पर स्थित परियोजना स्थल का दौरा किया। यहां सब्सिडी राशि के अलावा, योजना के तहत अनिवार्य आवश्यकता के रूप में लगाए गए साइनबोर्ड पर परियोजना की कुल लागत 1,99,20,000 रुपये दिखाई गई है।

इसमें कहा गया है कि प्रमोटर का हिस्सा 49,80,000 रुपये था और मंत्री ने परियोजना के लिए एचडीएफसी बैंक से 1.49 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि अजमेर से भाजपा सांसद और 2024 से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे चौधरी ने एनएचबी योजना के तहत परियोजना पर काम शुरू करने के लिए मंजूरी हेतु 15 अप्रैल 2025 को आवेदन किया था। इस योजना के तहत परियोजना को 14 दिन बाद, 29 अप्रैल 2025 को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी।

यह योजना चुनिंदा सब्जियों और फूलों की खेती से बड़े पैमाने पर लाभ कमाने के उद्देश्य से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आती है, जिसे 2014-15 में शुरू किया गया था। इसका संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो चौधरी के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।

श्री चौधरी की 16,592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती की परियोजना, एनएचबी द्वारा 2025 में बागवानी फसलों के उत्पादन और कटाई के बाद प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास नामक योजना के तहत अनुमोदित 467 परियोजनाओं में से एक है।

समुद्री रास्ते से विदेश पहुंच रहा आमः बंगनप्पल्ली आमों की खैप पहुंची सिंगापुर, कम लागत से निर्यात के नए अवसर की जागी उम्मीद

आईसीएआर और एपीईडीए के समुद्री प्रोटोकॉल से आम के निर्यात की लागत में कमी आई है, निर्यात के नए अवसर बढ़ेंगे

नई दिल्ली। अब तक हवाई मार्ग से हो रहे फलों के निर्यात को नही राह मिली है। आईसीएआर और एपीईडीए ने समुद्री प्रोटोकॉल से आम के निर्यात की नई पहल शुरु की है, जिससे लागत में कमी आई है। बीते हफ्ते आंध्र प्रदेश से 4.3 टन बंगनापल्ली आम एक खास ठंडे कंटेनर के जरिए समुद्र के रास्ते सिंगापुर भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस सफल प्रयास से विकसित देशों में रसीले और विदेशी किस्म के भारतीय आमों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। समुद्री शिपमेंट तकनीक आमों की शेल्फलाइफको 30 दिनों तक बढ़ाती है, जिससे वैश्विक निर्यात के नए अवसर खुलते हैं।

भारत के ताजे फलों के निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में, भारतीय आम समुद्री मार्ग से सफलतापूर्वक सिंगापुर पहुंच गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किफायती और बड़े पैमाने पर आम के निर्यात का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

सिंगापुर में भारतीय आमों को उनके उत्कृष्ट स्वादए सुगंध और गुणवत्ता के लिए बहुत महत्व दिया जाता है और बंगनप्पल्ली और केसर जैसी किस्मों की उपभोक्ताओं में काफी मांग है। निर्यात को अधिक किफायती और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, आईसीएआर.केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ ने एपीईडीए के सहयोग से आम निर्यात के लिए एक वैज्ञानिक समुद्री शिपमेंट प्रोटोकॉल विकसित किया है।

इस पहल के तहत, आंध्र प्रदेश से बंगनप्पल्ली आमों की 4.3 टन की खेप को रेफ्रिजरेटर कंटेनर के माध्यम से सिंगापुर निर्यात किया गया। समुद्री मार्ग से माल ढुलाई की लागत में काफी कमी आती है, जो हवाई मार्ग से 150-250 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में लगभग 13-20 रुपये प्रति किलोग्राम है। इससे उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात अधिक किफायती हो जाता है और विदेशी उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य मिलता है।

आईसीएआर और सीआईएसएच द्वारा विकसित प्रोटोकॉल में अवशेष.मुक्त उत्पादनए कृषि पद्धतियों वैज्ञानिक कटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और कटाई के बाद के प्रबंधन को शामिल करते हुए एक संपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को एकीकृत किया गया है। निर्यात किए गए फलों को गर्म जल उपचार से गुज़ारा गया, जो आईसीएआर और सीआईएसएच द्वारा विकसित एक तकनीक है। यह तकनीक फलों की शेल्फलाइफबढ़ाती है, रोगों की घटनाओं को कम करती है और लंबी दूरी के परिवहन के दौरान फलों की गुणवत्ता बनाए रखती है।

फलों के लगाने से लेकर कटाई तक, अवशेष.सुरक्षित उत्पादन पद्धतियों और आईसीएआर और सीआईएसएच द्वारा विकसित जैविक नियंत्रण तकनीक फ्यूसीकोंट का उपयोग करते हुए, आईसीएआर और सीआईएसएच् विशेषज्ञों द्वारा बागों की वैज्ञानिक निगरानी की गई। एपीडा द्वारा अनुमोदित पैकेजिंग इकाई में प्रसंस्करण से पहले फलों की गुणवत्ता और अधिकतम अवशेष सीमा की जांच की गई।

आईसीएआर और सीआईएसएच ने समुद्री मार्ग से माल भेजने की परिस्थितियों में आमों की शेल्फ लाइफ को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक बढ़ा दिया है। सिंगापुर से भेजी गई खेप ने 16 दिनों में अपनी यात्रा पूरी की और फल 20.1 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस के साथ उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचे ए उनमें कोई रोग नहीं पाया गया और उनकी गुणवत्ता हवाई मार्ग से भेजे गए आमों के बराबर थी।

इस खेप की सफ्लता से सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और अन्य बाजारों में भारतीय आम के निर्यात के विस्तार में सुविधा होने की उम्मीद है, जहां वर्तमान आयात 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, साथ ही यूएई जैसे बड़े बाजारों में अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है, जिनका मूल्य 20-25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ।

किफायती समुद्री शिपमेंट प्रोटोकॉल के विकास से भारत के आम निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलने, किसानों की आय में वृद्धि होने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने और बागवानी क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यह सफ्ल खेप किफायती और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स समाधानों के माध्यम से भारत के ताजे आम के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दुनिया भर के किसानों, निर्यातकों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

हवाई भाड़े के मुकाबले समुद्री रास्ता है बहुत सस्ता

भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। दुनिया भर में पैदा होने वाले कुल आम का 40प्रतिशत हिस्सा भारत में उगता है। लेकिन, भारत अपने कुल आम का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा ही विदेशों में बेच पाता है। इसका मुख्य कारण हवाई जहाज का महंगा भाड़ा है।

वर्तमान में अमेरिका और यूरोपीय देशों में आम हवाई जहाज से भेजा जाता है, जिसका भाड़ा 150 से 250 रुपये प्रति किलो आता है। इसके कारण हमारा आम विदेशों में बहुत महंगा हो जाता है। वहीं, समुद्री रास्ते से यह भाड़ा सिर्फ13 से 20 रुपये प्रति किलो रहने का अनुमान है। मुंबई के तट से पश्चिम एशियाई देशों तक समुद्री रास्ते से पहुंचने में लगभग 5 दिन का समय लगता है। जानकारों के अनुसार, समुद्री रास्ते से आम का सफल निर्यात होने पर अमेरिका, यूरोप के साथ-साथ सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग जैसे बाजारों में आम बेचना आसान हो जाएगा। इन देशों में भारत के बंगनापल्ली और केसर आम की बहुत मांग है।

नई तकनीक से 35 दिनों तक ताजा रहेगा आम

समुद्र के रास्ते आम भेजने में समय ज्यादा लगता है, इसलिए इसे लंबे समय तक ताजा रखना जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ और एपीडा मिलकर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे आम 35 दिनों तक खराब नहीं होगा। सिंगापुर भेजे गए आमों को गर्म पानी और वॉश तकनीक से धोया गया था। यह तकनीक आम को ज्यादा दिन तक ताजा रखती है और उस पर लगे कीड़ों को मार देती है। वाफा फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रुट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एकराम हुसैन कहते हैं कि समुद्री रास्ते के विकास से ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े बाजारों में हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत के आम अपने रस और मीठे स्वाद के लिए जाने जाते हैं।

भारत में आम की बहुत बड़ी घरेलू खपत है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल आम उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं। भारत ने बीते वित्त वर्ष में 56.34 मिलियन डॉलर का आम निर्यात किया है। इस सीजन में कुल 45 देशों को आम भेजा है। समुद्री रास्ते की नई व्यवस्था से संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत जैसे पश्चिम एशियाई देशों में पहले से मौजूद 25 मिलियन डॉलर सालाना के बाजार का भी और विस्तार होगा।

विदेशी बाजारों की अलग.अलग शर्तें और जापान की रोक

अलग-अलग देशों में आम भेजने के लिए उसे अलग.अलग तरीकों से साफ करना पड़ता है। अमेरिका भेजे जाने वाले आमों को विकिरण से गुजारा जाता है, ताकि फल के अंदर के कीड़े और कीटनाशकों का असर खत्म हो जाए। वहीं, जापान और दक्षिण कोरिया भाप और गर्म पानी के उपचार की मांग करते हैं।

हालांकि, हाल ही में जापान ने 20 साल बाद भारत से ताजे आमों के आयात पर फिर से रोक लगा दी है। जापानी क्वारंटाइन निरीक्षकों के अनुसार, भारतीय उपचार केंद्रों में कीड़ों को मारने और कीटाणुशोधन की प्रक्रिया में कमियां पाई गई थीं।

1 जुलाई से बदलेगी गांवों की तस्वीर: ग्राम पंचायतों की रैंकिंग से तय होगा बजट

लागू होगा वीबी.जी राम जी एक्ट, ग्रामीण विकास योजनाओं में तालमेल के लिए सरकार ने की तैयारी

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

भोपाल/ नई दिल्ली। मप्र की ग्राम पंचायतों को मिलने वाले सरकारी बजट और फंड आवंटन की व्यवस्था 1 जुलाई से बदलने जा रही है। प्रदेश में अब पंचायतों को उनकी भौगोलिक स्थिति, विकास के स्तर और आबादी के आधार पर एए बी और सी तीन अलग.अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा।

यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के साथ मप्र में लागू होने जा रही केंद्र सरकार की नई योजना वीबी.जी राम जी (विकसित भारत ग्राम जी) योजना के तहत होने जा रहा है। इस नई व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार, इस नए वर्गीकरण का सबसे बड़ा फायदा उन पंचायतों को मिलेगा जो अब तक विकास की मुख्यधारा से दूर रही हैं।

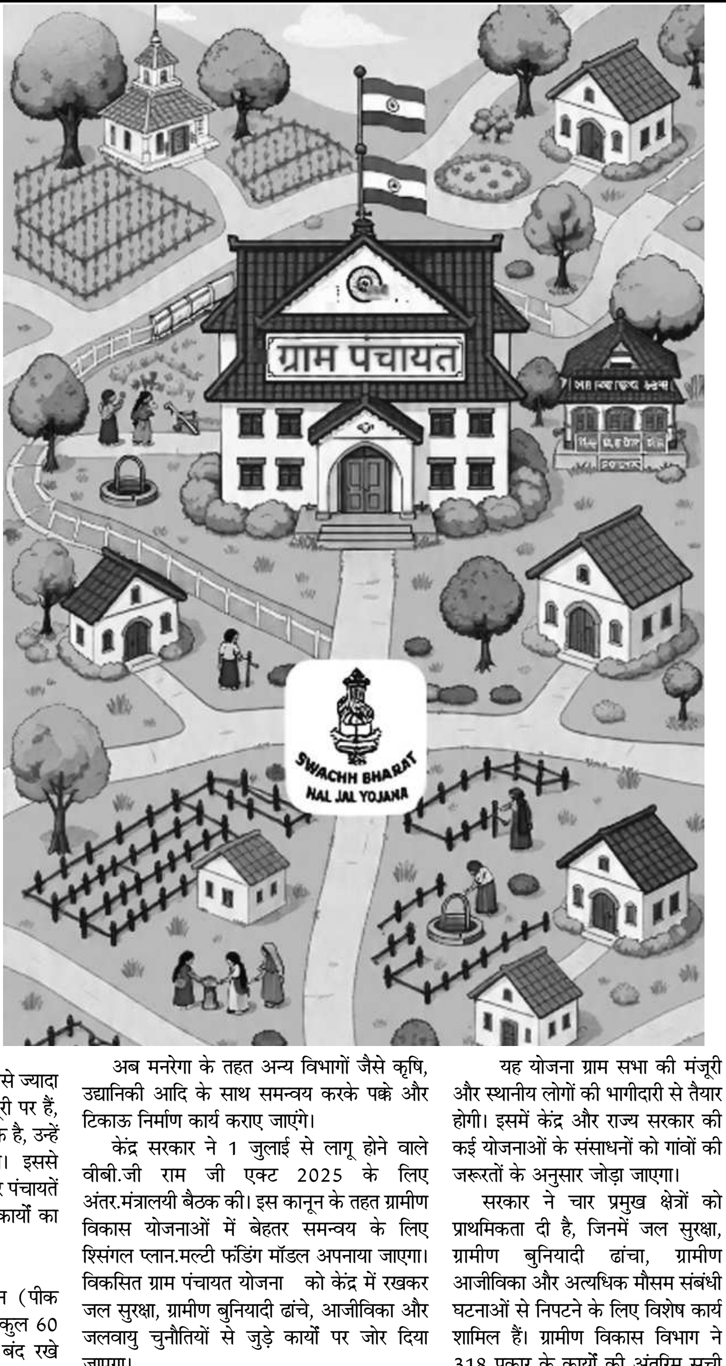

नई गाइडलाइन के तहत जो पंचायतें सबसे ज्यादा पिछड़ी हैं, जिला मुख्यालय से अत्यधिक दूरी पर हैं, या जहां एससी या एसटी की आबादी अधिक है, उन्हें सीश् कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इससे प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से रसूखदार पंचायतें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके विकास कार्यों का बड़ा बजट नहीं ले पाएंगी।

नो वर्क डेज को बांटा तीन भाग में

नई योजना में कृषि के व्यस्त सीजन (पीक एग्रीकल्चर पीरियड) के दौरान सालभर में कुल 60 दिनों तक मनरेगा के काम पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। इसे नो वर्क डेज नाम दिया है। मप्र में इसे तीन भाग में बांटा जा रहा है। रबी, खरीफके साथ मूंग कटाई के समय।

जबकि अब तक किसान खेतों के लिए मजदूर ढूंढते रहते थे और मजदूर मनरेगा के कामों में मसरूफ रहते थे, जिससे फसल चक्र प्रभावित होता था। ऐसे ही नई व्यवस्था में केवल गढ्डे खोदने या मिट्टी-मुरम के अस्थाई काम देने की बजाय ऐसे कार्यों पर फोकस किया जाएगा जिससे ग्रामीणों को स्थाई आजीविका मिल सके।

अब मनरेगा के तहत अन्य विभागों जैसे कृषि, उद्यानिकी आदि के साथ समन्वय करके पक्के और टिकाऊ निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लागू होने वाले वीबी.जी राम जी एक्ट 2025 के लिए अंतर.मंत्रालयी बैठक की। इस कानून के तहत ग्रामीण विकास योजनाओं में बेहतर समन्वय के लिए श्सिंगल प्लान.मल्टी फंडिंग मॉडल अपनाया जाएगा। विकसित ग्राम पंचायत योजना को केंद्र में रखकर जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका और जलवायु चुनौतियों से जुड़े कार्यों पर जोर दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर.मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई। बैठक में 18 मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों तथा नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और पंचायत आधारित विकास योजना को मजबूत बनाना था।

यह योजना ग्राम सभा की मंजूरी और स्थानीय लोगों की भागीदारी से तैयार होगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के संसाधनों को गांवों की जरूरतों के अनुसार जोड़ा जाएगा।

सरकार ने चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जिनमें जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ग्रामीण आजीविका और अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने 318 प्रकार के कार्यों की अंतरिम सूची भी जारी की है, जिनमें सिंचाई, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण संपर्क, सामुदायिक ढांचा और जलवायु अनुकूल विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि 1 जुलाई से यह नया ढांचा लागू होने के बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन में बेहतर तालमेल आएगा तथा गांवों के समग्र विकास को गति मिलेगी।

26 राज्यों ने बजट में किया प्रावधान

विकसित भारत जी राम जी योजना पर अमल के संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्रामीण रोजगार, श्रमिक सुरक्षा और गांवों के समग्र विकास को नई गति देने के लिए इस व्यापक वित्तीय और नीतिगत पहल की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही नई ऐतिहासिक व्यवस्था के तहत ट्रांजिशन पूरी तरह सुचारू श्रमिक.केंद्रित और बिना किसी व्यवधान के होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि यह केवल एक योजना का परिवर्तन नहीं है, बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक दिन भी कोई मजदूर बिना काम के न रहे और रोजगार, मजदूरी भुगतान तथा वैधानिक अधिकारों की गारंटी में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी।

उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पहले ही मनरेगा के तहत 30 हजार करोड़ रुण् आवंटित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त आज 95,692 करोड़ रुपए का इंटरिम अलोकेशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया। इस प्रकार कुल राशि 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी।

श्री चौहान ने कहा कि यह राशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, जिससे प्रत्येक पंचायत को लाखों रुपये का फंड उपलब्ध होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस धनराशि का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चिन्हित विकास कार्यों में किया जाए, जिससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल धन उपलब्ध नहीं करा रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि समय पर मजदूरी भुगतान हो, श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और विकास कार्यों में कोई व्यवधान न आए। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे पर्याप्त मात्रा में कार्यों को पूर्व स्वीकृति दें ताकि 1 जुलाई से ही काम तेजी से शुरू हो सके।

आवंटन इस प्रकार हैं.

आंध्र प्रदेश 7,707.21 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 560.70 करोड़, असम 1,929.7 करोड़, बिहार 6,715.83 करोड़, छत्तीसगढ़ 3,354.85 करोड़, गोवा 3.70 करोड़, गुजरात 1,540.54 करोड़, हरियाणा को 590.19 करोड़, हिमाचल प्रदेश 1,203.28 करोड़, झारखंड 2,705.64 करोड़, कर्नाटक 5,709.9 करोड़, केरल 3,136.44 करोड़ मध्य प्रदेश 6,252.03 करोड़, महाराष्ट्र 4,420.32 करोड़, मणिपुर 581.99 करोड़, मेघालय 1,155.09 करोड़, मिजोरम 611.65 करोड़, नागालैंड 287.85 करोड़, ओडिशा 3,763.80 करोड़ रुपए और पंजाब 1,331.61 करोड़, का आवंटन हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के लिए 7,581.87 करोड़, सिक्किम के लिए 97.57 करोड़, तमिलनाडु के लिए 7,585.49 करोड़, तेलंगाना के लिए 3,825.31 करोड़, त्रिपुरा के लिए 1,041.7 करोड़, उत्तर प्रदेश के लिए 9,721.48 करोड़, उत्तराखंड के लिए 626.43 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए 8,508.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। जिससे राज्यों को कुल 92,550.17 करोड़ रुपये मिलेंगे।

28 साल में 24591 किसानों और खेत मजदूरों ने केरल में की आत्महत्या, कर्ज बना सबसे बड़ी वजहः रिपोर्ट

नई दिल्ली। देश के केरल में कृषि संकट लगातार गहराता जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार 1995 से 2022 के बीच राज्य में 24,591 किसानों और खेत मजदूरों ने आत्महत्या की। यानी औसतन हर साल 1,069 लोगों ने अपनी जान गंवाई। रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ता कर्ज, खेती की बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन और फसलों के घटते दाम किसानों की परेशानी की बड़ी वजह बन रहे हैं। यह जानकारी महाराजा कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. मार्टिन पैट्रिक द्वारा लिखी गई पुस्तक कर्षिका केरलम पिन्निट्टा अरुपथु पथिट्टांडुकल में दी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन सेक्रेड हार्ट कॉलेज, थेवरा और ऑर्गेनिक केरल चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है।

देश की किसान आत्महत्याओं में 4.25 प्रतिशत हिस्सेदारी

रिपोर्ट के मुताबिक, 1995 से 2022 के दौरान देशभर में हुई किसान आत्महत्याओं में केरल की हिस्सेदारी 4.25 प्रतिशत रही। इनमें 92 प्रतिशत पुरुष थे, जो राष्ट्रीय औसत 80 प्रतिशत से काफी अधिक है। देशभर की बात करें तो 2023 की तुलना में 2024 में कृषि मजदूरों की आत्महत्या में मामूली कमी आई, लेकिन यह संख्या अब भी किसानों / खेती करने वालों से अधिक रही। आत्महत्या करने वालों में कम से कम 56 प्रतिशत कृषि मजदूर थे। यह पिछले पांच वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा अनुपात है

हाल के वर्षों में भी नहीं थमा संकट

अध्ययन के अनुसार, 2014 से 2022 के बीच भी केरल में 2,233 किसानों ने आत्महत्या की। सबसे अधिक मामले इडुक्की जिले में 453, पलक्कड़ में 404 और तिरुवनंतपुरम में 337 दर्ज किए गए। यह आंकड़े बताते हैं कि कृषि संकट अब भी गंभीर बना हुआ है।

कर्ज बना सबसे बड़ी समस्या

डॉ. मार्टिन पैट्रिक के अनुसार, किसानों की आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह कर्ज का बढ़ता बोझ है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कर्ज ही शुरुआत भी है और अंत भी बन गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि केरल की लगभग एक.तिहाई आबादी कर्ज में डूबी हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है।

किसानों पर लाखों रुपये का कर्ज

राष्ट्रीय नमूना सर्वे के अनुसार, केरल में 70 प्रतिशत किसान कर्जदार हैं। प्रति किसान औसत कर्ज करीब 2.2 लाख रुपये है। वहीं, केरल इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन के अध्ययन में यह औसत कर्ज 5.46 लाख रुपये बताया गया है। इसके अलावा, राज्य में प्रति परिवार औसत कर्ज 1.99 लाख रुपये है, जो देश में सबसे अधिक माना जाता है।

आय बढ़ी नहीं, बचत घट गई

नाबार्ड की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण परिवार की औसत मासिक आय 16,788 रुपये है। औसत मासिक खर्च 14,778 रुपये है। यानी हर महीने केवल 2,010 रुपये की बचत हो पाती है। यह बचत 2016-17 में 3,975 रुपये थी, जो अब लगभग 48 प्रतिशत घट चुकी है।

अलग-अलग फसलों के किसान प्रभावित

रिपोर्ट के अनुसार, केरल में केवल एक फसल नहीं बल्कि कई फसलों की खेती करने वाले किसान संकट का सामना कर रहे हैं। इडुक्की और वायनाड में काली मिर्च के किसानों को आयात बढ़ने से कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ा। इलायची, केला, अदरक और जायफल की फसलें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुईं। अनानास की फसल को जंगली जानवरों से नुकसान हुआ। रबर किसानों को बढ़ती लागत और कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ा। नारियल उत्पादकों को बढ़ती लागत और रोगों से नुकसान हुआ।

खेती का रकबा लगातार घट रहा

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केरल में खेती योग्य भूमि लगातार कम हो रही है। 1970-71 में धान की खेती 8.8 लाख हेक्टेयर में होती थी। 2024-25 में यह घटकर केवल 1.76 लाख हेक्टेयर रह गई। वर्तमान में राज्य में कुल खेती योग्य भूमि 19.67 लाख हेक्टेयर है। इसके कारण केरल अपनी सब्जियों की जरूरत पूरी करने के लिए भी दूसरे राज्यों पर काफी हद तक निर्भर हो गया है।

कृषि सुधार की जरूरत

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों की आय बढ़ाने, कर्ज का बोझ कम करने, फसलों का उचित मूल्य दिलाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो कृषि संकट और गहरा सकता है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता है। इन आत्महत्याओं से कहीं न कहीं देश का कृषि कार्य प्रभावित होने के साथ ही संकट के दौर से गुजरते नजर आ रहा है। हालांकि शासन स्तर पर खेती को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन इन प्रयासों के बीच भी आत्महत्याओं का सिलसिला नही रुकना सोचने पर मजबूर करता है।

सिर्फकर्ज ही नहीं, ये कारण भी जिम्मेदार अध्ययन में किसानों की परेशानी के पीछे कई अन्य कारण भी बताए गए हैं, जैसे. जलवायु परिवर्तन जंगली जानवरों का फसलों को नुकसान खेती की बढ़ती लागत फसलों के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव सरकारी नीतियों का प्रभाव

महाराष्ट्र में 2023 में 6,669 किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या कीः मंत्री

महाराष्ट्र। राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने 25 जून को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि महाराष्ट्र में 2023 में 6,669 किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की।

एनसीपी विधायक धर्मराव बाबा अत्रम द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि आत्महत्या से होने वाली मौतों के आंकड़े राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2023 के अनुमानों पर आधारित हैं।

मंत्री ने कहा, यह सच है कि आत्महत्या करने वालों में 4,150 किसान और 2,519 कृषि मजदूर थे। आत्महत्या करने वाले कृषि मजदूरों में से 77 महिलाएं थीं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कि क्या उन 29 खेतिहर मजदूरों की मृत्यु को सूची से बाहर रखा गया है, जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं थी। इसके जवाब में श्री पाटिल ने संक्षिप्त उत्तर देते हुए कहा, यह आंशिक रूप से सच है, बिना कोई स्पष्टीकरण या विवरण दिए।

कृषि क्षेत्र में होने वाली मौतों के मामलों के वर्गीकरण और क्या सभी पात्र कृषि श्रमिकों को आधिकारिक आंकड़ों में शामिल किया गया है, इस बारे में चिंताओं के बीच सरकार ने यह जवाब दिया।

मोदी सरकार में कल्याणकारी योजनाओं से सशक्तिकरण

भारत की शासन व्यवस्था से परिचित लोग यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी सक्षम नेतृत्वकर्ता सिद्ध हुए हैं। उनके नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान भारत ने अद्भुत प्रगति की है। बुनियादी ढांचे से लेकर गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, उद्योग, कृषि, विदेश नीति, रक्षा और डिजिटल इंडिया हो या सामाजिक क्षेत्र में हासिल उपलब्धियां इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन्हीं उपलब्धियों के दम पर वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं।

उनकी सफलताओं की सूची को एक स्तंभ में समेटना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू को रेखांकित करना ही सबसे उचित होगा, जिसने उनकी एक अलग पहचान बनाई। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही गरीब और हाशिए पर मौजूद वंचित वर्गों को अपनी प्राथमिकता बनाया और उनके उत्थान के लिए ऐसी योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर उतारा, जिससे इन वर्गों के जीवन की गुणवत्ता सुधरी है। उनके नेतृत्व में की गईं कई पहल संविधान के भाग चार में उल्लिखित राज्य नीति के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत उन उद्देश्यों से ही प्रेरित हैं, जो कल्याणकारी राज्य बनाने और विशेष रूप से गरीबों के लिए जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करती हैं।

मोदी की पहली क्रांतिकारी पहल थी प्रधानमंत्री जन-धन योजना। इसने वित्तीय समावेशन में एक नई क्रांति की। इसका यह बिंदु और भी संतोषजनक है कि जनधन में 56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं। इसने देश की आधी आबादी के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की राह प्रशस्त की है। इसी क्रम में मोदी का अगला बड़ा विचार था, स्वच्छ भारत मिशन। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को शौचालयों के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की गई। ऐसा ही एक कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली रसोई गैस उपलब्ध कराना था। इस योजना के जरिये 10.5 करोड़ परिवार लाभार्थी बने हैं। यह सही है कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण सब्सिडी वाले सिलिंडरों की संख्या में कटौती की गई, लेकिन उम्मीद है कि जब पेट्रोलियम उत्पादों का प्रवाह सामान्य होगा, तो इसे बहाल किया जाएगा। हर घर नल से जल कार्यक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी की आपूर्ति करना है। अब तक 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 73 प्रतिशत के पास यह सुविधा पहुंचाई जा चुकी है।

कोविड काल में संघर्ष कर रहे लोगों को सहारा देने के लिए आरंभ की गई मुफ्त राशन योजना भी 81 करोड़ लोगों का सहारा बन चुकी है। इस योजना ने मुश्किल वक्त में गृहिणियों के समक्ष चुनौतियों को विकराल नहीं होने दिया। इन सभी योजनाओं का मर्म समझें तो इनकी संकल्पना कहीं न कहीं महिलाओं की मुश्किलों को ध्यान में रखकर की गई। जैसे गरीब ग्रामीण परिवारों में महिलाओं को शौच के लिए घर से बाहर और अक्सर गांव से बाहर तक जाना पड़ता था। शौचालय की सुविधा से उन्हें बड़ी राहत मिली। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए दूर.दराज जाना पड़ता था और धुएं में खाना पकाना पड़ता थाए लेकिन रसोई गैस से उनकी ये दुश्वारियां दूर होने के साथ ही भोजन पकाना भी कहीं आसान हो गया है।

सरकार ने विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए एक.तिहाई सीटों के आरक्षण के लिए कानून को आगे बढ़ाने की भली मंशा दिखाने के साथ ही सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित 17 महिला अधिकारियों का पहला बैच हाल ही में सशस्त्र बलों में कमीशन किया गया।

25 को देवशयनी एकादशी, शादियों पर लगेगा चार माह का ब्रेक

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन(सोनी) अजमेर

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

अजमेर। इन दिनों चल रहे विवाह सहित गृहप्रवेश, जनेऊ संस्कार सहित अन्य मांगलिक आयोजनों पर जल्द ही रोक लगने जा रही है। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास शुरु होने वाला है, जिसके चलते आगामी चार माह तक मांगलिक आयोजनों पर ब्रेक लग जाएगा।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप सोनी (जैन) अजमेर के अनुसार देवशयनी एकादशी को चातुर्मास का पहला दिन होता है। चातुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इस वजह से 4 महीने तक विवाहए सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन आदि जैसे कार्य नहीं करते हैं। चातुर्मास का समापन देवउठनी एकादशी को होता है, उसके बाद से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।

इस बार ज्येष्ठ अधिकमास होने से विवाह आदि मांगलिक कार्यों के मुहूर्त काफी कम थे। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने के बाद 25 जुलाई देवशयनी एकादशी तक मांगलिक कार्यों के लिए आखिरी एक माह बचा है। इसके बाद चातुर्मास का आरंभ हो जाएगा और मांगलिक कार्यों के लिए चार माह इंतजार करना पड़ेगा। आषाढ़ मास में 15 जुलाई को बुध पुष्य नक्षत्र के विशिष्ट संयोग में गुप्त नवरात्र का आरंभ होगा। पुष्य नक्षत्र में शुरू होने वाली गुप्त नवरात्र साधना आराधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भड्डाली नवमी पर गुप्त नवरात्र की पूर्णाहुति होगी।

चातुर्मास से पहले मांगलिक कार्यों के लिए यह आखिरी शुभ मुहूर्त है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन शुभ मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती है।

चातुर्मास 2026 का प्रारंभ

वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 9. 12 बजे से होगा। यह तिथि 25 जुलाई दिन शनिवार को 11. 34 तक तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है, इसलिए चातुर्मास का प्रारंभ 25 जुलाई से होगा।

चातुर्मास में कौन से महीने आते हैं

चातुर्मास के समय में आषाढ़ के एकदशी से पूर्णिमा तक के दिन होते हैं। इसके बाद सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह आते हैं।

चातुर्मास का समापन

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चातुर्मास का समापन देवउठनी एकादशी यानि देवउत्थान एकादशी को होता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है। वैदिक पंचांग में देखा जाए तो इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7. 15 बजे से लेकर 21 नवंबर को सुबह 6. 31 बजे तक रहेगी। देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है, ऐसे में चातुर्मास का समापन 20 नवंबर शुक्रवार को होगा।

चातुर्मास में मांगलिक कार्यों पर क्यों लग जाती है रोक?

चातुर्मास के पहले दिन जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से देवी और देवता सो जाते हैं। वे 4 माह तक शयन करते हैं। भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी को योग निद्रा से बाहर आते हैं, तो सभी देवी और देवता भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए देवी और देवताओं का जागृत अवस्था में होना जरूरी है, इसलिए चातुर्मास के 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई, जनेऊ आदि जैसे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है।

29 जुलाई को गुरुपूर्णिमा

आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरुपूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इसे भैरव पूर्णिमा भी कहा जाता है। मालवा की लोकपरंपरा में इस दिन मंदिर तथा घरों में कुल परंपरा अनुसार भैरव पूजा का विधान है। सुबह गुरुकुल व आश्रमों के गुरुपाद पूजा के आयोजन होंगे।

वर्ग पहेली नं. 24 बाएं से दाएं

1. प्रफुल्लित, आनंदित (2)
3. भारत की राष्ट्रीय मुद्रा (3)
6. छटपटाहट (3)
7. भय, आतंक (4)
9. वायु, पवन, वात (2)
10. अनोखा, अनूठा (4)
12. मुँह व शरीर की भाव.भंगिमा (4)
13. समुद्र (4)
14. श्रीकृष्ण का एक नाम (4)
16. धावन, दौड़ने की प्रतियोगिता (2)
17. हमेशा, हर साँस पर (4)
19. संवेदनशील, कोमल हृदय वाला (3)
20. भारत का राष्ट्रीय ध्वज (3)
21. लालिमा (2)

ऊपर से नीचे.

2. जिस फूल में सौ पत्ते हों, कमल (4)
3. चांदी जैसा उज्ज्वल (4)
4. स्मृति (2)
5. इसलिए, अतः (4)
8. अपने देश का (5)
11. निराधार (5)
13. रत्न (4)
14. बड़े भाग्यवाला, सौभाग्यशाली (4)
15. घर, भवन या इमारत बनाने की कला (4)
18. बुद्धि (4)

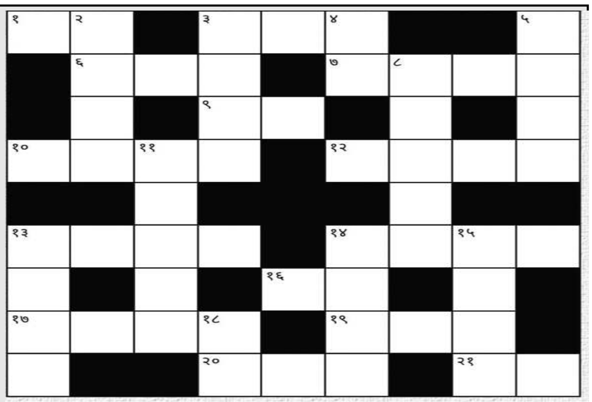

वर्ग पहेली नंबर 23 का हल

ना	व		क	म	ल			नि
	ट	ख	ना		ता	न	पू	रा
	वृ		ग	धा		र		धा
प	क्ष	पा	त		न	भ	च	र
		ठ				क्ष		
रा	ष्ट्र	प	ति		नौ	क	रा	नी
ज		ढ़ा		म	सि		ज	
पा	र्श्व	ना	थ		खि	ड़	की	
ट			ल	ठि	या		य	दि

सूखे की आहट: जून में नही बरसे बादल देश में सामान्य से 41 फीसदी कम बारिश

प्रमुख जलाशयों में क्षमता के मुकाबले 27.5 प्रतिशत पानी

नई दिल्ली।
देश में मानसून की सुस्त शुरुआत और वर्षा की कमी का असर प्रमुख जलाशयों के जल भंडारण पर भी साफ नजर आने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार इस मानसून सीजन में 1 जून से 19 जून के बीच देशभर में सामान्य से 41 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। देश के 36 मौसमीय क्षेत्रों में से 23 में सामान्य से कम वर्षा हुई है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, 18 जून तक देश के 166 प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी उनकी कुल भंडारण क्षमता का केवल 27.49 प्रतिशत रह गया है। यह पिछले वर्ष इसी अवधि के जल भंडारण का 86.62 फीसदी है। हालांकि, जलाशयों में मौजूदा जल भंडारण सामान्य स्तर की तुलना में 13 फीसदी अधिक है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मध्य भारत में वर्षा की कमी सामान्य के मुकाबले 64 फीसदी तक पहुंच गई है। गुजरात में सामान्य से 90 फीसदी, कोंकण एवं गोवा में 84 फीसदी तथा मध्य महाराष्ट्र में 81 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे इन क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत में प्री.मानसून बारिश से राहत मिली है, जहां 1 जून से 19 जून के बीच वर्षा सामान्य से केवल 4 फीसदी कम रही है। इसके विपरीत, पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत में इस अवधि के दौरान सामान्य से 45 फीसदी कम बारिश हुई है। दक्षिण भारत में भी वर्षा सामान्य से 22 फीसदी कम दर्ज की गई है।

4 जून को तीन दिन की देरी से केरल पहुंचने के बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई। 8 जून को मानसून कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को पार करते हुए महाराष्ट्र और तेलंगाना में प्रवेश कर गया थाए लेकिन पिछले 8.10 दिनों से इसकी प्रगति लगभग थमी हुई है।

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 23 जून के आसपास मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों के साथ.साथ छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है।

यदि अगले कुछ सप्ताह में मानसून की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो खरीफ फसलों की बुआई, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अल नीनो के प्रभाव के कारण इस साल मानसून सीजन में सामान्य के मुकाबले 90 फीसदी वर्षा की आशंका जताई गई है, जो खरीफ के साथ-साथ और आगामी रबी सीजन के लिए भी बड़ी चुनौती है।

हालांकि, पिछले वर्षों में भारत की जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में देश के लगभग 55 प्रतिशत सकल फसल क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 2010-11 में यह आंकड़ा करीब 40 प्रतिशत था। इसके बावजूद बारिश और जलाशयों के जल स्तर में कमी कृषि क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है।

कम बारिश की आशंका को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाने की बात कही है। देश के लगभग 315 जिलों को संवेदनशील मानकर वहां विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं। जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है और तालाबों, बांधों तथा जलाशयों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं।

पानी की हर बूंद की बचत जरूरी है और इसी को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे बदलते मौसम के अनुसार खेती की योजना बनाएं ताकि नुकसान कम हो सके।

भविष्य में मॉनसून की अस्थिरता बढ़ने के आसार, ताकत कम होने का भी अंदेशा भी जताया जा रहा है।

भारत में बड़ी आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है। अगर मानसून कमजोर रहता है तो धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों पर सीधा असर पड़ता है। इससे खाद्य उत्पादन कम हो सकता है और कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है।

क्या है अल नीनो, जिससे डर रही है दुनिया

सरल शब्दों में, समुद्र की सतह और उसके नीचे दोनों जगह गर्मी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जो बताते हैं कि अल नीनो की स्थिति मजबूत होती जा रही है। यह संकेत है कि अल नीनो जल्द सक्रिय हो सकता है।

वैज्ञानिक रूप से देखें तो अल.नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यीय क्षेत्र में घटने वाली उस मौसमी घटना का नाम है, जिसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और हवा पूर्व की ओर बहने लगती है। इसकी प्रभाव न केवल समुद्र पर बल्कि वायुमंडल पर महसूस किया जाता है। देखा जाए तो यह मौसम का एक गर्म चरण है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहले से गर्म हो रही दुनिया को और ज्यादा गर्म कर सकता है।

जलवायु वैज्ञानिकों के मुताबिक इस घटना के चलते समुद्र का तापमान चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है।

सरल शब्दों में कहें तो जब मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से अधिक होने लगता है, तो उसे अल नीनो कहा जाता है। यह बदलाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। कई क्षेत्रों में सूखा बढ़ता है, कहीं बाढ़ आती है और खेती पर दबाव बढ़ जाता है। यह अपने साथ एक अनिश्चितता का संदेश लेकर आता है।

विशेषज्ञों ने कहा,किसानों के सामने पहले से महंगे उर्वरक और ईंधन की समस्या है, ऐसे में मौसम की मार संकट को और गहरा कर सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो बनने की संभावना अब पिछले महीने की तुलना में ज्यादा स्पष्ट हैए लेकिन यह कितना शक्तिशाली होगा इसको लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। मौजूदा अनुमान के मुताबिक, किसी भी श्रेणी कमजोर, मध्यम या मजबूत के अल नीनो के बनने की आशंका 37 फीसदी से अधिक नहीं है।

इतिहास बताता है कि सबसे शक्तिशाली एल नीनो तब बनते हैं, जब गर्म समुद्र और वायुमंडल के बीच मजबूत तालमेल गर्मियों के दौरान लगातार बना रहे।

2026 में ऐसा होगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल बढ़ते तापमान तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी वजह से मानसून, खाद्य आपूर्ति और वैश्विक बाजारों पर भी असर पड़ेगा।

वैज्ञानिकों का कहना है कि शक्तिशाली अल नीनो का मतलब हमेशा बड़े असर नहीं होता। यह सिर्फ कुछ मौसमी बदलावों, जैसे सूखा या ज्यादा बारिश, की आशंका को बढ़ाता है।

कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी वजह से एशिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। सच कहें तो यह महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन लाखों किसानों की पेशानी पर उभरने वाली चिंता की लकीरें हैं, जिनकी जिंदगी और जीविका सीधे तौर पर आसमान से बरसने वाली बूंदों पर टिकी है।

देखा जाए तो मानसून के दौरान अल नीनो के उभरने का मतलब है कि एशिया के कई हिस्सों में बारिश कम हो सकती है, तापमान बढ़ सकता है और धान जैसी फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। भारत में पहले ही मानसून के कमजोर रहने की आशंका जताई गई है।

अलनीनों का क्या रहेगा प्रभाव

प्रशांत महासागर के गर्भ में पनप रही गर्मी ने दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो के बनने की संभावना 82 फीसदी है, जबकि इसके सर्दियों तक बने रहने की संभावना 96 फीसदी बताई गई है। यह ऐसे समय सामने आया है, जब भारत में पहले ही कमजोर मानसून की आशंका जताई जा रही है।

प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय हिस्से में समुद्र की सतह और उसके नीचे लगातार बढ़ती गर्मी संकेत दे रही है कि अल नीनो जल्द सक्रिय हो सकता है। यह घटना केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दुनिया भर के मौसम चक्र को प्रभावित करती है।

यह मौसमी घटना न केवल वैश्विक तापमान को बढ़ाएगी, बल्कि भारतीय मानसून के चरित्र को भी बदल सकती है। भारत जैसे देशों में इसका असर कम बारिश, सूखे, फसल नुकसान और बढ़ती खाद्य कीमतों के रूप में दिख सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अल नीनो मानसून के दौरान मजबूत हुआ, तो फसलों की पैदावार घट सकती है। ईंधनञखाद की बढ़ती कीमतों के बीच, यह बदलाव खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है।

इससे पहले भी 2015 और 2023 जैसे वर्षों में अल नीनो के कारण मॉनसूनी बारिश कमजोर रही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक, 2026-27 केवल मौसम की चुनौती नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और महंगाई के रूप में बड़ी परीक्षा बन सकता है।

सुबह खेत में खड़े किसान की नजर सबसे पहले आसमान पर जाती है, क्योंकि बादल सिर्फपानी नहीं, उनके लिए सालभर की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन इस बार वैज्ञानिक पहले ही चेता चुके हैं कि मानसून कम मेहरबान रह सकता है। ऊपर से प्रशांत महासागर के गर्भ में पनप रहा अल नीनो दुनिया के मौसम को बदलने की तैयारी में है, और इसका असर खेतों से लेकर रसोई तक महसूस हो सकता है।

अमेरिकी मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा चेतावनी के मुताबिक, प्रशांत महासागर में अल नीनो के पनपने की आहट तेज हो गई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक मई से जुलाई 2026 के बीच इसकी शुरुआत की आशंका 82 फीसदी तक पहुंच चुकी है। इसके बाद सर्दियों तक जाते.जाते (दिसंबर 2026 से फरवरी 2027) तक इसके बने रहने की आशंका 96 प्रतिशत बताई गई है।

बता दें कि 12 मई 2026 को जापान के मौसम ब्यूरो ने इस बात की 90 फीसदी आशंका जताई है कि अल नीनों के गर्मियों तक उभरने का अंदेशा है।

पिछले कुछ महीनों से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य के करीब बना हुआ था और स्थिति तटस्थ थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने देखा है कि भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के भीतर सतह के नीचे लगातार गर्मी बढ़ रही है। यह संकेत है कि अल नीनो जल्द सक्रिय हो सकता है।

कमजोर मानसून से पिछड़ी खरीफ बुवाई, 23 % पिछड़ी धान और तिलहन की बुवाई

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली।

दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी शुरुआत का असर खरीफ फसलों की बुवाई पर साफ दिखाई दे रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप के 25 जून तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में खरीफ फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 53.74 लाख हेक्टेयर कम रही है। इस अवधि तक कुल 182.72 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह आंकड़ा 236.46 लाख हेक्टेयर था। यानी बुवाई में करीब 22.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

जून में मानसून के आगमन के साथ ही देश में खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो जाती है, जो जुलाई के आखिर तक चलती है। इस साल जून में मानसून की प्रगति काफी धीमी रही और दो सप्ताह से यह मध्य भारत में अटका हुआ है। जून माह के दौरान देश में सामान्य से 43 फसदी कम वर्षा हुई और अधिकांश कृषि क्षेत्र बारिश में कमी से जूझ रहे हैं।

धान, तिलहन और कपास में सबसे बड़ी गिरावट

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसारए धान की बुवाई 25.75 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले वर्ष के 34.41 लाख हेक्टेयर से 8.65 लाख हेक्टेयर कम है।

दलहन का रकबा भी 21.46 लाख हेक्टेयर से घटकर 14.92 लाख हेक्टेयर रह गया। अरहर, उड़द और मूंग की बुवाई में गिरावट दर्ज की गई है।

मोटे अनाज का कुल रकबा 31.84 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले वर्ष के 36.07 लाख हेक्टेयर से कम है। हालांकि ज्वार के रकबे में कुछ बढ़ोतरी हुई है, जबकि मक्का का रकबा घटकर 15.71 लाख हेक्टेयर रह गयाए जो पिछले वर्ष 18.61 लाख हेक्टेयर था।

तिलहन फसलों की स्थिति सबसे अधिक प्रभावित रही। कुल तिलहन बुवाई 36.41 लाख हेक्टेयर से घटकर 16.99 लाख हेक्टेयर रह गई। इसमें सबसे बड़ी गिरावट सोयाबीन में दर्ज की गईए जिसका रकबा 19.97 लाख हेक्टेयर से घटकर 6.92 लाख हेक्टेयर रह गया। मूंगफली की बुवाई भी 15.29 लाख हेक्टेयर से घटकर 8.87 लाख हेक्टेयर रह गई।

कपास की बुवाई 45.36 लाख हेक्टेयर से घटकर 29.66 लाख हेक्टेयर रह गईए यानी इसमें 15.70 लाख हेक्टेयर की कमी आई है।

इसके विपरीत गन्ने का रकबा 56.64 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 57.31 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि जूट एवं मेस्ता की बुवाई में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 जून को जारी बुलेटिन में कहा है कि अगले दो.तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

आईएमडी ने कोंकण एवं गोवा,ए मध्य महाराष्ट्र, उप.हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं.कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। दूसरी ओर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तथा हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में लू की स्थिति बने रहने की संभावना भी जताई गई है।

जुलाई के पहले पखवाड़े पर टिकी नजर

जून में मानसून की धीमी प्रगति के बाद अब खरीफ बुवाई की उम्मीदें जुलाई के पहले पखवाड़े पर टिकी हैं। यदि अगले कुछ दिनों में व्यापक और नियमित वर्षा होती है तो धान सोयाबीन कपास और मक्का की बुवाई में तेजी आ सकती है और शुरुआती कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है। लेकिन यदि मानूसन आगे भी कमजोर रहा तो इसका असर न केवल बुवाई बल्कि पैदावार और कृषि उत्पादन पर भी पड़ सकता है।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक, विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन, जिला खरगोन से प्रकाशित, पिननं. 451001 (मप्र) संपादक विवेक जैन, RNI No. MPHIN/ 2022/85285. मोबा. नं. 9826225025, 94254 89337 (सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)